दिल्ली में सरकारी दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों की बिक्री

252. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्यान्नों की बिक्री हेतु कितनी सरकारी दुकानें हैं और उनके द्वारा प्रत्येक माह कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके माध्यम से बेचे जा रहे खाद्यान्नों के मूल्यों में कोई वृद्धि की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जा रहे दूध के मूल्य में की गई कमी की तरह ही खाद्यान्नों के बिक्री मूल्य में भी कमी करने का विचार रखती है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री और वाणिज्य में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) उचित दर दुकानें 3437 हैं (सरकारी तथा सहकारी एजेंसियों और निजी व्यापारियों द्वारा चलाई जाती हैं) वे इस समय प्रति माह लगभग 16000 मि० टन चावल और 60,000 मी० टन गेहूं का वितरण करती हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के उपभोक्ता मूल्य निम्नवत् रहे हैं :

उपभोक्ता मूल्य

(रु० प्रति कि० ग्रा०)

चावल (जिस तारीख से प्रभावी हैं)	गेहूं (जिस तारीख से प्रभावी है)
3.46 (1-5-90)	2.48 (1-5-90)
3.93 (25-6-90)	2.96 (28-12-91)
4.86 (28-12-91)	3.00 (4-9-92)
4.90 (4-3-92)	3.52 (11-1-93)
5.53 (11-1-93)	

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सुपर बाजार में कार्यरत महिला कर्मचारी

253. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1993 की स्थिति के अनुसार सुपर बाजार में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शाखा-वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक महिला कर्मचारी के नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति और नियुक्ति की तिथि के संबंध में श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि सुपर बाजार में महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है और उन्हें अन्य सुविधाओं और लाभों से वंचित रखा जा रहा है और उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सुपर बाजार प्रशासन ने सरकार द्वारा पहले घोषित प्रसुविधाओं से अपनी महिला कर्मचारियों को वंचित रखा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (कमालु द्दीन अहमद) : (क) से (ग) ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है, जिसमें सुपर बाजार में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या, उनकी श्रेणी, नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति और नियुक्ति की तारीख दी गई है (देखिए परिशिष्ट 169, अनुपत्र संख्या 1) अनसूचित जाति के 37 और अनुसूचित जनजाति के 8 कर्मचारी हैं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वे पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का रिकार्ड नहीं रख रहे हैं।

(घ) जी नहीं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों से कम वेतन नहीं दिया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Dearness Allowances to employees of Super Bazar

254. **SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN**: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dearness Allowance to Super Bazar Employees has still not been paid by the General Manager despite jodgement of the court given more than 12 months back ;

(b) whether it is also a fact that a sum of Rs. 85,000 has to be paid on this account and this amount have been utilised by the General Manager for his personal office and residential furnishing purpose ;

(c) if so, the reasons therefor and by when payment of D.A. is to be released by the General Manager ;

(d) the steps taken or proposed to be taken by Government against the General Manager for misuse of fund ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) Super Bazar has reported that 96 employees approached Labour Court for computing the amount of D.A. payable in accordance with Baweja Award but the Labour Court upheld the claims of only 78 employees of the store. The arrears of D.A. were paid to concerned 78 employees in October, 1992.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

सुपर बाजार में मिलावटी और गलत ब्रांड की वस्तुएं

255. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार द्वारा बेची जा रही अनेक वस्तुएं मिलावटी और गलत ब्रांड की पाई गई हैं;

(ख) दिल्ली प्रशासन को इस संबंध में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) दिल्ली प्रशासन ने उन नमूनों के बारे में क्या कार्यवाही की है जिन्हें मिलावटी और गलत ब्रांड का पाया गया;

(घ) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, जो मिलावटी और गलत ब्रांड की पायी गई;